

Dr. Shalish Kumar
Dept. of Economics
Raja Singh College
Gwalior

(1)

B.A. (Hons.)
Economics

कर प्रणाली का प्रगामीपन - एक विचार Progressivity of taxation (a comment)

किसी एक विचारधीन कर के प्रगामीपन का अर्थ है उसके प्रमाणन का विवेचन इससे पहले किया जा चुका है। परंतु कई बार यह प्रश्न उठता है कि समस्त कर-प्रणाली के प्रगामीपन को किस प्रकार मापा जा सकता है। इस संबंध में विद्वानों ने कई विकल्प सुझाए हैं। परंतु उनमें से किसी एक को सर्वोत्तम घोषित करना संभव नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि वितरणीय असमानताएँ कर-प्रणाली के प्रगामीपन के अतिरिक्त कई अन्य कारकों द्वारा भी प्रभावित होती हैं।

मान लें कि राष्ट्रीय आय और कर-देयता क्रमशः Y और T के बराबर हैं तथा इस प्रकार कराधान की औसत दर T/Y के बराबर है। इसी प्रकार यदि यदि राष्ट्रीय आय में $M(Y)$ बढ़ोतरी होने पर सकल कर-देयता में $M(T)$ की वृद्धि होती है, तो कराधान की सीमांत दर $M(T)/M(Y)$ के बराबर होगी।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर-प्रणाली के प्रगामीपन के मुख्य प्रमाणन नीचे दिए गए हैं।

1. यदि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ-साथ कराधान की औसत दर में भी बढ़ोतरी होती है, तो कर प्रणाली को प्रगामी माना जाएगा। इस विधि में कराधानों को उनकी आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार उनकी कर-देयता आंकी जाती है।

2. प्रो. पीस (Professor Pigou) ने कर के प्रगामीपन की आंकी के लिए सीमांत कर-दर को प्राथमिकता दी है। इस प्रमाणन के अनुसार यदि कराधानों की आय के बढ़ने के साथ-साथ सीमांत कर-दर भी बढ़ जाती है, तो कर प्रणाली को प्रगामी माना जाएगा।

11.7.20

(2)

3. यह भी सम्भव है कि कर-प्रणाली में निम्न आय वालों के लिए कर-दर का प्रवधान हो। इस स्थिति में राष्ट्रीय आय के वृद्धि पर सीमांत दर के स्थिर रहते हुए भी औसत दर बढ़ती जाती है। अतः आय, औसत कर-दर और सीमांत कर-दर का एकसाथ प्रयोग करते हुए निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं।

	प्रणामी	अनुपाती	परचगामी
(कर-देयता में अनुपातिक परिवर्तन) / (राष्ट्रीय आय में अनुपातिक परिवर्तन)	> 1	= 1	< 1
सीमांत कर / औसत कर	> 1	= 1	< 1
सीमांत कर - औसत कर	> 0	= 0	< 1

4. प्रो० मन्ग्रोव और थिन (Muscgrave and Thin) के अनुसार कर-प्रणाली का प्रणामीपन (कर-देयता में अनुपातिक वृद्धि / राष्ट्रीय आय में अनुपातिक वृद्धि) के बराबर होता है। स्पष्ट है कि यह प्रमाण कर-देयता की राष्ट्रीय आय के प्रति लैच के बराबर है। इसे कर-देयता प्रणामीपन (Taxability Progression) की संज्ञा दी जाती है।

5. एक अन्य प्रमाण के अनुसार कर प्रणाली का प्रणामीपन $[(1 - \text{सीमांत कर दर}) / (1 - \text{औसत कर दर})]$ के अनुपात के बराबर है। इस प्रमाण को शेष आय प्रणामीपन (Residual Income Progression) की संज्ञा दी जाती है।

6. प्रो० डाव्टन ने सापेक्षिक औसत अंतर (Relative Mean Difference) के द्वारा कर-प्रणाली के प्रणामीपन की मापने का सुझाव दिया। इस सुझाव के अनुसार विभिन्न आय वर्गों की औसत दरों का सापेक्षिक औसत अंतर कर-प्रणाली के प्रणामीपन का एक उत्तम प्रमाण है। परंतु इस प्रमाण की भुटि यह है कि जब धनी वर्गों की कर-देयता में कमी तथा निर्धन वर्गों की कर-देयता में वृद्धि होती जाए, तो भी इस प्रमाण के अनुसार कर-देयता के

प्रणामीपन में वृद्धि होती है।

7. एक अन्य प्रमाण की केन्द्रीकरण प्रमाण कहा जाता है। इस विधि में करदाताओं की कई आय वर्गों में वॉल्यू के पश्चात् प्रत्येक आय-वर्ग के लिए कर की औसत दर अनुमानित की जाती है। तत्पश्चात् इन अनुमानों को एक रेखाचित्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। x-अक्ष पर आय वर्गों की बढ़ती आय के क्रम से तथा y-अक्ष पर उसी क्रमानुसार उनकी कर-देयताओं की औसत दरें प्रस्तुत करने पर जो वक्र प्राप्त होता है, उसे केन्द्रीकरण वक्र (Concentration curve) कहा जाता है।

इस विधि विधि के अनुसार कर-प्रणाली का प्रणामीपन =

$1 - 2$ (केन्द्रीकरण वक्र और दोनों अक्षों के घित क्षेत्रफल) के बराबर है। इस प्रमाण के बढ़ते मूल्य को कर प्रणाली के प्रणामीपन में वृद्धि मना जाता है।

8. एक अन्य विधि के अनुसार राष्ट्रीय की वितरणीय असमता के दो अनुमान लगाए जाने चाहिए: एक करारोपण से पहले के लिए (G) और दूसरा करारोपण से बाद के लिए (G*)। इस दशा में =

$$(G^* - G) / G$$

को कर-प्रणाली के प्रणामीपन का प्रमाण माना जाता है।